



प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,

समग्र शिक्षा,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 03 सितम्बर, 2026

विषय: **वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत सामान्य मद में प्राप्त केन्द्रांश की फर्स्ट मदर सेंक्शन के सापेक्ष केन्द्रांश तथा संगत राज्यांश की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-समग्र शिक्षा/वित्त-बजट/3850/2026-27, दिनांक 19.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत लेखाशीर्ष -2202-01-113-01-0101-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राप्त केन्द्रांश की 1st Mother Sanction के सापेक्ष केन्द्रांश तथा संगत राज्यांश की धनराशि ₹0 48205.80 लाख स्टेट इम्पलीमेंटिंग सोसाइटी, समग्र शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) को स्वीकृत/अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत अनुदान सं0-71 के लेखाशीर्ष-2202-01-113-01-0101-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 462249.60 लाख (मूल प्राविधान धनराशि ₹0 513944.63 लाख में से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि ₹0 51695.03 लाख घटाते हुए) के सापेक्ष 1st Mother Sanction के रूप में धनराशि **₹0 48205.80 लाख (रुपये चार अरब बयासी करोड़ पांच लाख अस्सी हजार मात्र)** (केन्द्रांश धनराशि ₹0 28923.48 लाख एवं राज्यांश धनराशि ₹0 19282.32 लाख) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा, जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है।
- (2) योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार ही-प्रस्तावित धनराशि का व्यय किया जाएगा।
- (3) निर्धारित कार्यों से इतर धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा व किसी भी अनियमितता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (4) भौतिक प्रगति की रिपोर्ट एवं व्यय की गयी समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 2025 तथा योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-'लेखाशीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा-01- प्रारम्भिक शिक्षा-113-समग्र शिक्षा अभियान-01-केन्द्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रायोजित योजनाएं-0101- वेतनादि से भिन्न मदें (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-11-162-X-2026-27, दिनांक 31 अगस्त, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
 - 2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
 - 3- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
 - 4- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र०, लखनऊ।
 - 5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 6- मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, लखनऊ।
 - 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
 - 8- नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
 - 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ०प्र० शासन।
 - 10- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
 - 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल मणि यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।